प्रकाशन का 43 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार
ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 9 – 16 जुलाई 2018 मूल्य पांच रूपए

मण्डी से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को मकरझण्डू कहकर वीरभद्र ने की भाजपा की राह आसान

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष सुक्खु को पद से हटाने के लिये विधानसभा चुनावों से बहुत पहले से अभियान छेड़ रखा है। इसी अभियान के कारण विधानसभा चुनावों के लिये वीरभद्र सिंह को नेता घोषित किया गया था लेकिन फिर भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गयी जबकि पचपन टिकट वीरभद्र की सिफारिश पर दिये गये थे। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अधिकारिक तौर पर विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक भी बहुमत नहीं मिल पाया है। शायद इसीलिये कांग्रेस विधायक दल का नेता वीरभद्र की बजाये मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया है। इन विधानसभा चुनावों में वीरभद्र की व्यक्तिगत बडी उपलब्धि यही रही है कि वह अपनी पुरानी सीट शिमला ग्रामीण से अपने बेटे विक्रमादित्य को विधायक बनवा पाये हैं। स्वयं भी नये क्षेत्र अर्की से जीत हासिल कर पाये हैं। वैसे इस जीत को लेकर यह भी चर्चा रही है कि यहां पर भाजपा ने अपने दो बार लगातार जीत हासिल करने वाले विधायक गोविन्द शर्मा का टिकट काटकर वीरभद्र की जीत की राह आसान कर दी थी। इन चुनावों जहां कांग्रेस के अन्दर वीरभद्र के विरोधी हारे हैं वहीं पर कुछ उनके निकटस्थ भी हार गये हैं। विधानसभा चुनाव परिणामों के इस गणित से यह स्पष्ट संकेत उभरता है कि जिस ऐज और स्टेज पर वीरभद्र पहुंच चुके हैं वहां से जनता पर उनकी पकड़ अब पहले जैसी नहीं रह गयी है। यह सही है कि वह छः बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं और इस नाते प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ लोग उनको व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले आज भी हैं। लेकिन प्रदेश की जो समस्याएं आज है जिसका सबसे बड़ा कारण कर्ज का चक्रव्यूह है। यही नहीं आज स्कूलों में चौदह हज़ार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, सैंकड़ों स्कूलों को बन्द करना पड़ रहा है। यह सब कुछ बहुत हद तक उन्हीं के शासन काल की योजनाओं का परिणाम है। इस सब को लेकर अधिकांश जनता का आकलन क्या है शायद इसकी जानकारी वीरभद्र और कांग्रेस को व्यवहारिक तौर पर नहीं है।

आज कांग्रेस के अन्दर अगले नेता को लेकर एक बड़ा शून्य चल रहा है क्योंकि वीरभद्र ने अभी तक किसी एक का नाम अधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है। क्योंकि जब उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वह कांग्रेस के अन्दर भाजपा के आडवाणी और जोशी जैसे मार्गदर्शक नहीं बनना चाहते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अभी भी अपने को सत्ता के हकदारों में पहले स्थान पर मानकर चल रहे हैं लेकिन अपने इस मन्तव्य को वह सीधा घोषित नहीं कर रहे हैं परन्तु जिस तर्ज पर उन्होंने सुक्खु को हटवाने का अभियान छेड़ रखा है उससे तो पहला अर्थ यही निकलता है। अन्यथा वह पार्टी हित में वरिष्ठतम नेता होने के नाते कांग्रेस में सरकार और संगठन के नेतृत्व के लिये किसी को तो नामजद करते। लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर रहें है और साथ ही यह भी कह चुके हैं कि न तो वह स्वयं और न ही उनके परिवार से कोई दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ेगा तब इस सब के राजनीतिक मायने बदल जाते हैं। वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा मण्डी लोकसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार भी यदि यह लोग चुनाव लड़े तो स्वभाविक रूप से मण्डी से ही लड़ना होगा। लेकिन उन्होंने न केवल स्वयं लड़ने से मना किया है बल्कि कांग्रेस से जो भी लड़ेगा उसे अभी से ही मकर झण्डू कहकर उसकी हार की बुनियाद रख दी है। कांग्रेस हाईकमान उनके इस कथन को कैसे लेता है यह तो आगे पता चलेगा लेकिन निश्चित तौर पर मण्डी से होने वाले उम्मीदवार को मकरझण्डू कहकर भाजपा का रास्ता बहुत आसान कर दिया है। वीरभद्र जहां सुक्खु को हटाने की मांग कर रहे हैं वहीं पर उनके समर्थकों ने लोकसभा चुनाव वीरभद्र के नेतृत्व में लड़ने की मांग कर दी है। बल्कि शिमला से तो उनके समर्थकों ने सुरेन्द्र गर्ग को टिकट देने की मांग कर दी है। अभी ठियोग और सोलन की बैठकों में भाग लेने से पहले वीरभद्र ने हमीरपूर और कांगडा लोकसभा क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया है। कांगड़ा में सुधीर शर्मा और जी एस बाली उम्मीदवार के तौर पर सामने आये हैं लेकिन यहां वीरभद्र ने किसी एक का भी नाम सीधे नहीं लिया है। क्योंकि शायद बाली का सीधा विरोध करने से वह बच रहे हैं। लेकिन हमीरपुर में वह राजेन्द्र राणा के साथ खुलकर खड़े हैं और राणा स्वयं की जगह अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। वीरभद्र इस पर खामोश हैं। कांग्रेस के अन्दर वीरभद्र बनाम सुक्खु विवाद पर तो अब भाजपा ने चुटकीयां लेना शुरू कर दिया है क्योंकि इस विवाद से जहां कांग्रेस पक्ष जनता में कमजोर होता जा रहा है वहीं पर इससे भाजपा को अनचाहे ही

लाभ मिल रहा है। क्योंकि इस समय मण्डी लोकसभा सीट मुख्यमन्त्री जयराम के लिये प्रतिष्ठा का मामला होगा। विधानसभा चुनावों में मण्डी से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पायी है। क्योंकि चुनाव के दौरान ही अमित शाह ने यह घोषणा कर दी थी कि जयराम को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जायेगी। परन्तु अब सरकार बनने के बाद जयराम को सबसे पहली समस्या अपने ही चुनाव क्षेत्र से सामने आयी जब एस डी एम कार्यालय को लेकर जंजैहली में लोग आन्दोलन पर उतर आये। आज ही मण्डी की स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि यदि फिर से चुनाव हो जायें तो यह भाजपा पर भारी पडेंगे। यदि मण्डी से वीरभद्र या उनकी पत्नी में से कोई चुनाव लड़ता है तो भाजपा के लिये सीट जीतना कठिन हो जायेगा। ऐसे में वीरभद्र का मण्डी से चुनाव लड़ने से इन्कार करना और होने वाले उम्मीदवार को मकरझण्डू करार देना निश्चित रूप से जयराम और भाजपा की मदद करना बन जाता है।

इस वस्तुस्थिति को सामने रखते हुए यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि वीरभद्र ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के अन्दर संगठन के चुनाव क्यों रूके थे यह सब जानते हैं। अगले चुनाव कब करवाये जायेंगे यह हाईकमान के आदेशों से तय होगा। तो क्या वीरभद्र का सुक्खु पर हमला बोलना हाईकमान पर ही हमला नहीं बन जाता है। वीरभद्र एक लम्बे समय से आयकर और सी बी आई तथा ई डी के मामले झेल रहे हैं, यह मामले अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में वीरभद्र की सारी कारगुजारी को इन मामलों के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि ई डी के अटेचमैन्ट आदेश में जिस तरह के दस्तावेज सामने आ चुके हैं उनसे मामलों की गंभीरता का स्वतः ही अनुमान लग जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया एक लाख का जुर्माना

शिमला/शैल। देश में बढ़ती गारवेज समस्या का सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 28 मार्च को सभी राज्यों के तीन माह के भीतर इस संद्धर्भ में बनाई गयी योजना से शीर्ष अदालत को अवगत करवाने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के बाद 12 जुलाई को यह मामला जस्टिस मदन वी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की खण्डपीठ में लगा था। लेकिन इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से गारवेज प्रबन्धन को लेकर न तो कोई योजना अदालत के समक्ष रखी गयी और न ही सरकार की ओर से अदालत में कोई पेश हुआ। अदालत ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की यह अजीब स्थिति है जहां न तो राज्य सरकारें अदालत के निर्देशों की अनुपालना कर रही है और न ही भारत सरकार के वन एवम् पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देशों को मान रही हैं। इस टिप्पणी के साथ ही राज्य सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। हिमाचल सहित दस राज्यों पर भी यह जुर्माना लगा है। इस तरह का जुर्माना लगाना सीधे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है क्योंकि 28 मार्च को अदालत ने योजना बनाकर उसे पेश करने के आदेश दिये थे।

प्रदेश उच्च न्यायालय में भी इस दौरान जितने गंभीर मामले आये हैं अदालत ने उन पर सरकार से जवाब तलब किया है उन अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालय ने सरकार के शपथ पत्रों पर अप्रसन्नता ही व्यक्त की है। इनमें महत्वपूर्ण मामले वनभूमि अतिक्रमण, अवैध निर्माण, शिमला के सफाई कर्मचारियों की समस्या, शिमला की पेयजल संकट, स्नोडन की पार्किंग समस्या, कसौली में अदालत के आदेशों की अनुपालना और अब शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी का मामला रहे हैं। यह सारे मामले में अदालत में पहुंचे हैं और लगभग सभी मामलों में सरकार पर तथ्यों को छुपाने के आरोप लगे हैं। बहुत सारे मामलों में शैल यह शपथ पत्र जनता के सामने रख भी चुका है। लेकिन अब जब सर्वोच्च न्यायालय सरकार के आचरण का कड़ा संज्ञान लेते हुए जुर्माना लगाने पर विवश हो जाये तो निश्चित रूप से प्रशासन की नीयत और नीति पर सवाल उठेंगे ही।

अभी सरकार को सत्ता में आये केवल छः माह का ही समय हुआ है। इस अवधि में सरकार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नही लग पाया है। मंत्री और मुख्यमन्त्री बराबर जनता से संपर्क में जुटे हुए है। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार होने का कोई पुख्ता संदेश जनता में नही जा पाया है क्योंकि इस दौरान जो भी बड़े फैंसले सरकार ने लिये हैं उनमें कहीं न कहीं ऐसा कुछ घट गया है जिससे सरकार की छवि पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। विकास के नाम पर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि एशिया विकास बैंक से 4378 करोड़ के ऋण का वायदा लेना ही रहा है जबकि इस वायदे को पूरा होने के लिये एक लम्बा सफर तय करना है और दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तिय संस्थाओं ने विकासशील देशों को ऋण के रूप में भी वित्तिय सहायता देने से हाथ पीछे खींच लिये हैं। जब से डॉलर के मुकाबले में रूपये की कीमत मे कमी बढ़ी है उसी के साथ यह हुआ है इसका प्रभाव देश के हर राज्य पर पड़ेगा यह तय है। इसलिये कर्ज को उपलब्धि बनाकर प्रचारित करना कोई बहुत समझदारी नही है क्योंकि कल को यदि यह पूरे ऋण नही मिल पाते हैं तब इसका कोई भी जवाब जनता को स्वीकार्य नही हो पायेगा। फिर जनता के सामने यह भी नही रखा गया है कि पर्यटन और बागवानी जिन दो क्षेत्रों में इस ऋण से निवेश किया जाना है उन क्षेत्रों में ऋण पर ही आधारित पहले से ही कितनी योजनाएं चल रही हैं और इससे प्रदेश के राजस्व में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और आगे कितने समय में कितनी हो पायेगी तथा पिछले ऋण की इससे आये राजस्व से कितनी भरपायी हो पायी है।

अनुसंधान तथा नवीन तकनीक के लाभ खेतों तक पंहुचाने आवश्यक:महेन्द्र सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि

हिमाचल की विविध जलवायुगत अनुकूलता से लाभान्वित होने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान तथा नवीन तकनीक के लाभों को खेतों तक पहुंचाना होगा। महेन्द्र सिंह ठाकुर डॉ. यश्वन्त सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में विभिन्न निरीक्षण करने के उपरान्त विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एंव अन्य को सम्बोधित कर रहे थे।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जलवायुगत परिस्थितियां विभिन्न फलों, फूलों तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए सर्वथा अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारे प्रयासों की सफलता कृषि वैज्ञानिकों के योगदान पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को न केवल अनुसंधान तथा नवीन तकनीक को खेतों तक पहुंचाना होगा अपितु किसानों एवं बागवानों को इनके उपयोग की दिशा में प्रशिक्षित भी करना होगा।

बागवानी मंत्री ने कहा कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के ऊर्जावान नेतृत्व में प्रदेश सरकार 6 माह की अल्पावधि में ही केन्द्र सरकार से प्रदेश के लिए विकास की सशक्त योजनाएं स्वीकृत करवाने में कामयाब रही है। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 1688 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वीकृत की है। यह परियोजना कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी विकास की नई इबारत लिखने में कामयाब होगी।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ पेयजल एंव सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार के सत्त प्रयासों एवं केन्द्र सरकार की उदार सहायता से हिमाचल को पेयजल एवं सिंचाई क्षेत्र के लिए अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिए वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सवंद्धन एवं आवश्यकतानुसार पुन: निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। वर्षाजल संग्रहण, पेयजल तथा सिंचाई क्षेत्र के लिए 4751 करोड़ रुपए की एक परियोजना केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यह परियोजना भी स्वीकृत हो जाएगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 3267 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 1900 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने इससे पूर्व विश्वविद्यालय के विभिन्न उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा वैज्ञानिकों को इस दिशा में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में चन्दन का पौधा भी रोपा।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एच.सी. शर्मा ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव राजेश मारिया, विभिन्न संकायों के अध्यापक, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियन्ता संजीव कौल, अन्य अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भाखड़ा विस्थापितों को नई पुनर्वास नीति बनाये सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से बिलासपुर नगर भाखड़ा बांध विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मण्डल विधायक सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में मिला। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री को भाखड़ा बांध विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत करवाया।

प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य भूमि भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई परन्तु दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने भाखड़ा बांध के लिए अपनी जमीन दी। उन्हें भी अपने पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि विस्थापितों को केवल 900 से 1800 वर्ग फुट के प्लॉट ही आबंटित किए गए हैं जो उनके समुचित पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है।

प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस कारण बिलासपुर देश का एकमात्र शहर है जहां की जनसंख्या में 0.04 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह कमी भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए भूमि की उपलब्धता व लोगों के स्थानांतरण गमन के कारण उत्पन्न हुई है।

प्रतिनिधि मण्डल ने भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए नई नीति तैयार करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया तथा कहा कि पूर्व सरकार द्वारा तैयार की गई नीति विस्थापितों को न्याय दिलाने में असमर्थ साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'NOTICE INVITING TENDERS'

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division HP.PWD., Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on **08/08/2018 up to 11.00 AM.** And the same shall be opened on the same day at **11.30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on **07/08/2018 up to 4.00 P.M** and the application for issue of tender form shall be received on **06/08/2018 up to 12.00 noon**.
The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Sr.No.	Nameof work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money	Time Limit	Cost of tender form
1.	Construction of Saprul to Salan via Jaman Khola Harizan Basti Km. 0/00 to 2/400. (SW:-C/O 8.00 Mtrs. Span culvert at Rd 1/ 490 (Saprul side abutment).	4,95,600/-	10000/-	Three Months	350/-
2.	C/O link road from Neugal Bridge to Hanglow via Latwala Km. 0/00 to 5/00. (SW:- C/O R/Wall at Rd 0/725 to 0/735).	61,741/-	1300/-	Two Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-1430/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

राज्यपाल ने प्रदान किए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन शिमला में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आई.एल एण्ड एफ.एस के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जिन कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वह उनके कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से नजर आना चाहिए और उनके कार्य में और निखार व भिन्नता आनी चाहिए, इसे ही सही अर्थों में कौशल विकास कह सकते हैं। कुशलता व कर्म का योग ही कौशल कहलाता है। इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से जो कर्मचारियों ने सीखा है उसे कैसे प्रस्तुत करें, यह व्यवहार में आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी को, वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपना कार्य पूर्ण समर्पण व आत्मभाव से करना चाहिए। क्योंकि, जो व्यक्ति कर्मयोगी है उसे सभी सम्मान देते हैं। उन्होंने कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सभी के लिए उदहारण प्रस्तुत करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री भावी पीढ़ी को कौशल विकास से जोड़ना चाहते हैं, जिससे अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर लोगों के दिलों में स्थान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा क्षेत्र में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वे, जो अपनी कार्यकुशलता से अन्यों को प्रभावित करते हैं और दूसरे केवल समय व्यतीत करते हैं। लेकिन, कार्यकुशल व्यक्ति समाज और संस्थान के लिए मजबूत कड़ी होते हैं।

कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे 50 हैंडपम्प

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जनहित एवं विभिन्न पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं के सवर्द्धन के दृष्टिगत सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा की जाएगी। महेन्द्र सिंह ठाकुर कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत कुम्हारहट्टी में स्थानीय भाजपा मण्डल एवं लोगों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा महत्वाकांक्षी 'जल से कृषि को बल' योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। योजना के तहत प्रदेश में चैक बांध एवं तालाब निर्मित किए जाएंगे। प्रदेश में पेयजल योजनाओं पर इस वर्ष 275 करोड़ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 2572 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुरूप 50 हैंडपम्प भी समयबद्ध सीमा में स्थापित किए जाएंगे।

सरकारी भूमि अतिक्रमण मामलों पर जल्द कारवाई करें अधिकारी

हमीरपुर/शैल। उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह भू- राजस्व मामलों से सम्बंधित जन शिकायतों का तत्परता से निपटारा करें ताकि प्रशासन की लोगों में बेहतर छवि बनने के साथ उनका प्रशासन के प्रति विश्वास भी बना रहे। वह राजस्व अधिकारियों की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि सम्बंधित एसडीएम प्रत्येक मामले को तहसीलदार या नायब तहसीलदार के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें तथा गंभीर व संवेदनशील मामलों को समय पर उन्हें भेजें ताकि ऐसे प्रत्येक मामले में उनके स्तर पर त्वरित कार्यवाही कर समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। उन्होंने सभी एसडीएम को उनके अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों की की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अपने-2 क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ट्रैफिक प्लान तैयार करने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अगर कोई अड़चन आ रही है तो सम्बंधित उपमंडल के लोक निर्माण विभाग, आईपीएच विभाग, डीएसपी, व्यापार मंडल , टैक्सी तथा ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा सदस्यों को विश्वास में लेकर उचित हल निकालें।

उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अन्य मामलों बारे लोगों को जागरूक करें तथा इनके निष्पादन के लिए प्राथमिकता प्रदान करें। इन मामलों में प्रत्येक माह नायब तहसीलदार द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक लें। उन्होंने सभी एसडीएम को कहा कि वह प्रत्येक माह दो दिन नियमित रूप से कोर्ट लगाए ताकि लंबित पड़े मामलों को कम किया जा सके।

उपायुक्त ने एचआरटीसी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह जिला में प्रत्येक बस अडडे पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए डस्टबिन स्थापित करने के साथ-2 स्वच्छता पर आधारित साईन बोर्ड लगाएं। इसके अतिरिक्त जाहू तथा भोटा बस अडडों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने को भी कहा गया ताकि जो लोग या दुकानदार कूड़ा-कर्कट निर्धारित स्थल पर न फैंककर बस स्टैंड पर अस्वच्छता का माहौल पैदा कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह पन्द्रह दिन के भीतर भोटा बस स्टैंड को चकाचक करें तथा उसके बाद जिला के अन्य सभी बस अडडों पर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित बनाएं। इसके अतिरिक्त जिला के सभी बस अडडों पर एचआरटीसी के जिला अधिकारियों की मोबाईल नम्बर लिस्ट लगाने के भी निर्देश दिए गए ताकि लोग बस स्टैंड से सम्बंधित किसी भी कार्य के लिए अधिकारियों से आसानी से सम्पर्क कर सकें।

पर्यटन की दृष्टि विकसित किया जाएगा चौपाल क्षेत्र:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए पर्यटन परियोजनाएं प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिमला जिला के चौपाल एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विकास को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास व कल्याण के लिए वचनबद्ध है और छः महीनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने 49 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसान परिवार से सम्बंध रखते हैं और आम जन-मानस की विकास आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को पर्यटन विकास के लिए 1900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है और पहली बार प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेज चौपाल के लिए 1.25 करोड़ रुपये, आईटीआई चौपाल में तीन नए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा नागरिक अस्पताल चौपाल के बिस्तरों की क्षमता 50 से 100 करने की घोषणा की। उन्होंने चौपाल में मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय खोलने की भी घोषणा की।

जय राम ठाकुर ने क्रमशः 62.30, 48 लाख, 146 लाख व 103 लाख रुपये की लागत से निर्मित चौपाल में एसडीपीओ भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराहां स्तर-1 के भवन, क्यारटु नाला से कफोरना बाम्टा सड़क और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल के विज्ञान भवन के लोकार्पण किए।

मुख्यमंत्री ने सीआरएफ के तहत 10 करोड़ रुपये की लागत से सैंज-चौपाल, नेरवा-फेडज़ सड़क को चौड़ा करने व सुदृढ़ करने की आधारशिला रखी। उन्होंने 529 लाख रुपये की लागत से चौपाल में बनने वाले आजीविका केन्द्र व उत्पादन केन्द्र, 6.45 करोड़ रुपये की लागत से रीउणी (साजनाल) से खांगना सड़क की मेटलिंग व टायरिंग, 3.49 करोड़ रुपये की लागत से मड़ोग से दशोली सड़क की मेटलिंग व टायरिंग की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने मड़ोग-मातल सड़क पर 195.30 लाख रुपये की लागत से लोहाणा खड्ड पर निर्मित होने वाले 19 मीटर लम्बे आरसीसी टी-बीम पुल, 70 लाख रुपये की लागत से केलवी से लोहाणा सड़क की मेटलिंग व टायरिंग, 408.38 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां की विज्ञान प्रयोगशाला तथा 120.19 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धबास के भवन की भी आधारशिलाएं रखीं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मिलेगी हर सम्भव सहायता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला के धर्मशाला तथा देहरा में स्थापित की जा रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य में तेजी लाने के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रही केन्द्रीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 303-37-74 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है जिसमें से 278-43-79 हैक्टेयर वन भूमि है और 24-93-95 हैक्टेयर सरकारी भूमि है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाएंगे ताकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर को स्थापित करने के लिए 81.79 हैक्टेयर वन भूमि बदलने के लिए सैद्धान्तिक रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि देहरा में विश्वविद्यालय का दक्षिण परिसर स्थापित करने के लिए पहले ही 34 हैक्टेयर गैर वन भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्रा) धर्मशाला के नए भवन को केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अस्थाई आधार पर उपलब्ध करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि देहरा की 81.79 हैक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित करने के लिए भारत सरकार को प्रतिपूर्ति वन रोपण क्षतिपूर्ति, एनपीवी, वृक्षों की लागत व विभागीय शुल्कों के रूप में 17.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति में तेजी लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए एम्स भी स्वीकृत किया है, जो बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 681 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है और अन्य सम्बन्धित मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 112 बीघा अतिरिक्त भूमि की मांग की है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिए तत्काल आवश्यक पग उठाने के निर्देश दिए ताकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र स्थापित किया जा सके।

परमाणु-सोलन फोरलेन कार्य मार्च 2019 तक पूरा करे :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने 63 राष्ट्रीय राजमार्गों में से 58 राष्ट्रीय राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए सैद्धान्तिक तौर पर कुल 69 राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्य प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि शीघ्र इनका कार्य आरम्भ किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान राष्ट्रीय उच्च मार्गों का सड़क घनत्व औसत 47.65 किलोमीटर प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है जबकि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय औसत 38.40 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। राज्य में 69 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बाद प्रदेश में सड़क घनत्व 125.11 प्रति हजार किलोमीटर हो जाएगा। वर्तमान में राज्य में 2653 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बाद यह बढ़कर 6965 किलोमीटर हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य पूरा होने से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों को सेब और अन्य उत्पादों की ढुलाई के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रोहडू-चिड़गांव-लरोट-चांशल-डोडरा-क्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से न केवल उत्तराखण्ड में हरिद्वार/चार धाम जैसे धार्मिक स्थानों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा बल्कि राज्य में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन राजमार्ग के निर्माण कार्य में विलम्ब पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़क पर अतिरिक्त श्रम शक्ति और मशीनरी को तैनात कर कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर यातायात का भारी प्रवाह है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से परमाणु-सोलन फोरलेन के कार्य को पूरा करने के लिए कहा ताकि मार्च, 2019 तक इसे पूरा किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को वन और अन्य ढांचों को हटाने के बारे में त्वरित स्वीकृतियां सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित परियोजनाओं को पूरा करने में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। उन्होंने कहा कि निष्पादन एजेंसियों को सड़क के ऐसे हिस्सों की पहचान करनी चाहिए जिस पर आसानी से कार्य किया जा सकता है तथा जिन्हें विभिन्न मंजूरियां प्रदान की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं केन्द्र सरकार से फोरलेन परियोजनाओं व अन्य सम्बन्धित मामालों के शीघ्र कार्यान्वयन का मामला उठाएंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से शिमला में राज्य कैंसर संस्थान स्वीकृत करने का अनुरोध

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से भेंट की तथा भारत सरकार से शिमला में राज्य कैंसर संस्थान स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को 1250 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किए गए मानकों से अधिक है। उन्होंने इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च के लिए केन्द्र सरकार से 9.5 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला के आईजीएमसी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशियल्टी खण्ड के लिए धनराशि जारी करने की भी मांग की।

विपिन सिंह परमार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-108 में केन्द्र द्वारा 20 प्रतिशत का योगदान दिया जा रहा है, जिसे पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत 90 प्रतिशत किया जाना चाहिए। जे.पी. नड्डा ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा शीघ्र मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बी. के. अग्रवाल तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

सरकार ने जताई बाबा कांशी राम के घर को स्मारक बनाने की इच्छा

शिमला/शैल। पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम की जयन्ती के अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यदि बाबा कांशी राम के परिवार के सदस्य उनके जिला कांगड़ा के डाडासीबा में उनके पैतृक गांव गुरनवाड़ में स्थित उनके जर्जर पर पड़े पुराने घर को राज्य सरकार को सौंपने के लिए सहमत हो तो प्रदेश सरकार इस घर का जीर्णोद्धार कर इसे एक स्मारक के रूप में विकसित करेगी, जो बाबा कांशी राम के लिए श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम द्वारा देश की स्वाधीनता के लिए दिए गए योगदान के लिए देश व प्रदेशवासी हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कला, संस्कृति, भाषा अकादमी की ओर से पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम की जयंती पर प्रतिवर्ष साहित्य संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी अकादमी द्वारा राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में किया गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के कल्याण तथा उन्हें उचित सम्मान प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित स्मारक में बाबा कांशी राम से जुड़ी स्मृतियों, वस्तुओं तथा उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को संग्रहित किया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखा जा सके और वे उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना से परिचित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कांशी राम ने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कहा कि यदि बाबा कांशी राम के परिजन स्वीकार करें तो प्रदेश सरकार उनके इस पैतृक घर को न केवल उनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए एक केन्द्र के रूप विकसित करेगी, बल्कि यह स्थान पर्यटन के रूप में भी उभरेगा।

धावक सीमा को श्रेष्ठ प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करेगी सरकार: गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में यूथ ओलंपिक के लिए बैंकॉक में संपन्न क्वालीफायर मुकाबले में 3000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश की बेटी सीमा ने न केवल प्रतिष्ठित 'यूथ ओलंपिक' के लिए क्वालीफाई किया है अपितु प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सीमा व उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी है।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतकर सीमा ने आने वाले समय में प्रदेश के लिए न केवल यूथ ओलंपिक अपितु ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीमा को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगी ताकि वह भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश व देश का नाम ऊँचा कर सके।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश का युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री होने के नाते वह सरकार की ओर से सीमा को सहायता प्रदान करेंगे तथा खेल विभाग ने इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देश दे दिए है।

दूसरों के धन का अपहरण करने से स्वयं अपने ही धन का नाश हो जाता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या बढ़ते चुनाव खर्च पर रोक लगाई जा सकती है

इन दिनों ''एक देश एक चुनाव'' पर एक चर्चा चल रही है। यह सुझाव महामहिम राष्ट्रपति ने अपने संसद के संबोधन में दिया था। आज इस पर देश के चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वह इसके लिये तैयार है। विधि आयोग ने इस पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। कुछ दलों ने इससे सहमति जताई है तो कुछ ने असहमति। भाजपा और कांग्रेस ने इस पर अपना पक्ष आयोग के सामने नहीं रखा है। जिन दलों ने सहमति व्यक्त की है उन्होंने भी यह कहा है कि यह 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में ही हो जाना चाहिये। यह विचार अमली शक्ल ले पाता है या जुमला बनकर ही रह जाता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से बाहर आये इस विचार पर सत्तारूढ़ भाजपा की सहमति रही है या नहीं, या यह राष्ट्रपति का ही एक आदर्श विचार रहा है यह भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन यह विचार भाजपा के लिये एक बड़ा सवाल बन जायेगा क्योंकि इस विचार के लिये तर्क दिया जा रहा है कि इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। व्यवहारिक रूप से यह कदम सही है कि पांच साल के कार्यकाल में केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों तक को विधानसभा /लोकसभा/शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनावों का सामना करना पड़ता है। हर चुनाव में आदर्श संहिता लागू होती है और उतने समय तक विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इस गणित से सारे नहीं तो कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ हो जाने चाहिये। राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित में यह फैसला सर्वसम्मति से ले लेना चाहिये।

इस समय अधिकांश राज्यों में भाजपा की ही सरकारे हैं। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के पास बहुत कम राज्य है। बल्कि राष्ट्रीय दलों के नाम पर आज भाजपा और कांग्रेस दो ही दल रह गये हैं। क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्य से बाहर नहीं हैं। इस नाते भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही राष्ट्रहित में यह फैसला लेकर ''एक देश एक चुनाव'' को सार्थक बनाने में आगे आना चाहिये। यदि सही में ही हम समय और धन दोनों को बचाना चाहते हैं। इस समय चुनाव कितना महंगा हो गया है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अधिकारिक तौर पर हिमाचल जैसे राज्य के लिये लोकसभा के लिये यह खर्च सीमा 70 लाख कर रखी है। इसका अर्थ यह है कि चुनाव आयोग भी मानता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिये 70 लाख रूपये खर्च हो सकते हैं। खर्च की यह सीमा उम्मीदवार पर व्यक्तिगत तौर पर लागू होती है, राजनीतिक दल पर नहीं। राजनीतिक दल प्रति उम्मीदवार कई करोड़ खर्च कर सकता है उसके लिये कोई सीमा नहीं है। यहां पर यह सवाल सामने आता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो 70 लाख सफेद धन खर्च करके चुनाव लड़ सकता हो, शायद कोई भी नहीं। इसका यह अर्थ है कि चुनाव लड़ने के लिये व्यक्ति को किसी न किसी दल का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक दलों में आज चुनाव जीतने के लिये विचारधारा की बजाये चुनाव खर्च ही प्रमुख बन गया है। बल्कि इसके लिये होड़ लग जाती है कि कौन कितना अधिक खर्च करता है। राजनीतिक दलों के पास यह धन उद्योगपतियों से कैसे आता है और सरकार बनने पर किस शक्ल में वापिस किया जाता है और उसका भ्रष्टाचार, मंहगाई और बेरोजगारी पर कैसे प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इस पर महीनो बहस की जा सकती है और ढ़ेरों लिखा जा सकता है।

इसलिये आज जब यह मुद्दा राष्ट्रपति के माध्यम से सार्वजनिक बहस का विषय बना है तो इस पर ईमानदारी और गंभीरता से विचार कर लिया जाना चाहिये। इस संद्धर्भ में इसी के साथ जुड़े कुछ प्रसांगिक विषयों पर भी बात कर ली जानी चाहिये। इस समय विधानसभाओं से लेकर संसद तक आपराधिक छवि के सैंकड़ो माननीय बन कर बैठे हुए हैं। हर चुनाव के बाद यह आंकड़े आते हैं, चिन्ता व्यक्त की जाती है लेकिन परिणाम कोई नहीं निकलता। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निर्देश दे रखे हैं कि माननीयों से जुड़े आपराधिक मामलों में एक वर्ष के भीतर फैसला आ जाना चाहिये चाहे इसके लिये दैनिक आधार पर सुनवाई क्यों न करनी पड़े। इसके लिये विशेष अदालतें तक गठित करने की बात की गयी है लेकिन इसका अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। आपराधिक छवि के व्यक्ति का भी यही तर्क होता है कि वह जनता की अदालत से चुनकर आया है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या जब वह व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो क्या उसका सारा रिकॉर्ड जनता के सामने आ पाता है। क्या जनता को पता होता है कि उसके खिलाफ किस तरह के कितने आपराधिक मामले कब से चल रहे हैं। आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार ही न रहे इसको लेकर अभी तक न तो चुनाव आयोग, न ही सर्वोच्च न्यायालय और न ही संसद कोई व्यवस्था दे पायी है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश की जनता को यह वायदा किया था कि वह संसद को अपराधियों से मुक्त करवायेंगे। लेकिन यह वायदा पूरा नहीं हुआ है।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि राजनैतिक दलों में इस पर सहमति न बन पाये तो क्या यह विचार जुमला बनकर ही रह जाना चाहिये? आज चुनाव राजनैतिक दलों ने अपने बहुआयामी चुनाव प्रचार अभियानों से इतना महंगा बना दिया है कि यह केवल राजनैतिक दलों के ही बस की बात बनकर रह गया है। इसी कारण से हर राजनैतिक दल अपराधियों को अपना उम्मीदवार बना रहा है। धन और बाहुबल के सहारे जनता की अदालत से जीतकर आ रहे हैं। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिये जनता से ऐसे ऐसे वायदे कर लेते हैं जिन्हें कानूनन सार्वजनिक रिश्वतखोरी की संज्ञा दी जा सकती है लेकिन ऐसे वायदों का संज्ञान न तो चुनाव आयोग ले रहा है और न ही संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय। फिर ऐसे वायदों को सरकार बनने के बाद कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर बंदिश लगा दी जानी चाहिये कि सार्वजनिक रिश्वतखोरी की परिधि में आने वाले वायदे न किये जायें और ऐसा करने वाले दलों को चुनाव से बाहर कर दिया जाना चाहिये। दूसरा जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला किसी भी स्तर पर लम्बित है उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार न दिया जाये। राजनैतिक दलों पर भी चुनाव खर्च की सीमा होनी चाहिये और आचार संहिता की उल्लंघना को आई पी सी के तहत दण्डनीय अपराध बना दिया जाना चाहिये। यदि यह कदम भी उठा लिये जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विधानसभाओं से लेकर संसद तक के चरित्र में एक बड़ा बदलाव आ जायेगा। आज की व्यवस्था में तो उम्मीदवार के साथ आया शपथ पत्र भी सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बन पाता है। राजनीतिक दलों के आगे उनके अपने ही उम्मीदवार बौने बन कर रह जाते हैं। आज पहला सुधार तो यह लाना होगा कि उम्मीदवार दलों के व्यवहारिक बन्धक होकर ही न रह जायें।

यह लड़ाई है अच्छाई और बुराई की

अब हमें जागना ही होगा, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, इस समाज के लिए, सम्पूर्ण मानवता के लिए,अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए। हममें से हरेक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए।
हम सभी को अलख जगानी होगी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। और इसकी शुरूआत हमें अपने घर से खुद ही करनी होगी, उन्हें अच्छी परवरिश दे कर, उन में संस्कार डालकर, उनमें संवेदनशीलता, त्याग और समर्पण की भावना के बीज डाल कर, मानवता के गुण जगा कर।

''डॉ नीलम महेंद्र''

उच्चतम न्यायालय ने 9 जुलाई 2018 के अपने ताजा फैसले में 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के दोषियों की फाँसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसे उम्र कैद में बदलने की उनकी अपील ठुकरा दी है।

दिल्ली का निर्भया कांड देश का वो कांड था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। देश के हर कोने से निर्भया के लिए न्याय और आरोपियों के लिए फाँसी की आवाज उठ रही थी। मकसद सिर्फ यही था कि इस प्रकार के अपराध करने से पहले अपराधी सौ बार सोचे। लेकिन आज छ साल बाद भी इस प्रकार के अपराध और उसमें की जाने वाली क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2015 में बलात्कार के 34651, 2015 मे 38947 मामले दर्ज हुए थे। 2013 में यह संख्या 25923 थी। कल तक महिलाओं और युवतियों को शिकार बनाने वाले आज पाँच छ साल की बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में पॉक्सो ऐक्ट के तहत 2016 में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के 64138 मामले दर्ज हुए थे।

अभी हाल ही की बात करें तो सूरत, कठुआ, उन्नाव, मंदसौर, सतना।

इससे भी अधिक चिंता जनक बात यह है कि आज हमारे समाज में बात सिर्फ बच्चियों अथवा महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की नहीं है, बात इस बदलते परिवेश में 'अपराध में लिप्त' होते जा रहे हमारे बच्चों की है, और बात इन अपराधों के प्रति संवेदन शून्य होते एक समाज के रूप में हमारी खुद की भी है। क्योंकि ऐसे अनेक मामले भी सामने आते हैं जब महिलाएं धन के लालच में अथवा अपने किसी अन्य स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों को झूठे आरोपों में फँसाती है।

अभी हाल ही में एक ताजा घटना में भोपाल में एक युवती द्वारा प्रताड़ित करने पर एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले युवक यश पेठे द्वारा आत्महत्या करने का मामला भी सामने आया है। वो युवती ड्रग्स की आदी थी और युवकों से दोस्ती करके उन पर पैसे देने का दबाव बनाती थी।

कल तक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, आदतन अपराधी किस्म के लोग ही अपराध करते थे लेकिन आज के हमारे इस तथाकथित सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग और सभ्रांत घरों के बच्चे भी अपराध में संलग्न हैं।

ऐसा नहीं है कि अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी या मजबूरी के चलते आज हमारे समाज में अपराध बढ़ रहा हो। आज केवल एडवेन्चर या नशे की लत भी हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपराध की दुनिया में खींच रही है। इसलिए बात आज एक मानव के रूप में दूसरे मानव के साथ, हमारे गिरते हुए आचरण की है, हमारी नैतिकता के पतन की है, व्यक्तित्व के गिरते स्तर की है, मृत होती जा रही संवेदनाओं की है, लुप्त होते जा रहे मूल्यों की है, आधुनिकता की आड़ में संस्कारहीन होते जा रहे युवाओं की है, स्वार्थी होते जा रहे हमारे उस समाज की है जो पर पीड़ा के प्रति भावना शून्य होता जा रहा है और अपराध के प्रति संवेदन शून्य, बात सही और गलत की है, बात अच्छाई और बुराई की है, बात हम सभी की अपनी अपनी ''व्यक्तिगत'' जिम्मेदारियों से बचने की है,

एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक समाज के रूप में। बात अपनी ''व्यक्तिगत जिम्मेदारियों'' को ''सामूहिक जिम्मेदारी'' बनाकर बड़ी सफाई से दूसरों पर डाल देने की है, कभी सरकार पर, तो कभी कानून पर। लेकिन यह भूल जाते हैं कि सरकार कानून से बंधी है, कानून की आँखों पर पट्टी बंधी है और हमने अपनी आँखों पर खुद ही पट्टी बांध ली है।

पर अब हमें जागना ही होगा, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, इस समाज के लिए, सम्पूर्ण मानवता के लिए, अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए।

हममें से हरेक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। हम सभी को अलख जगानी होगी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। और इसकी शुरूआत हमें अपने घर से खुद ही करनी होगी, उन्हें अच्छी परवरिश दे कर, उन में संस्कार डालकर, उनमें संवेदनशीलता, त्याग और समर्पण की भावना के बीज डाल कर, मानवता के गुण जगा कर। क्योंकि यह लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, सही और गलत की।

आज हम विज्ञान के सहारे मशीनों और रोबोट के युग में जीते हुए खुद भी थोड़े थोड़े मशीनी होते जा रहे हैं। टीवी इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में जीते जीते खुद भी वर्चुअल होते जा रहे हैं। आज जरूरत है फिर से मानव बनने की, मानवता जगाने की।

27-28 जुलाई को शताब्दी का सबसे लंबा संपूर्ण चन्द्रग्रहण

मंगल और सूर्य एक दूसरे के आमने-सामने होंगे भारत के सभी हिस्सों से संपूर्ण चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा

शिमला। 27 – 28 जुलाई, 2018 को 1 घंटा 43 मिनट की कुल अवधि का संपूर्ण चन्द्रग्रहण होगा। इतने समय वाला यह इस शताब्दी (2001 एडी से 2100 एडी) का सबसे लंबा संपूर्ण चंद्रग्रहण होगा।

27 जुलाई को लाल ग्रह मंगल भी सामने होगा, जिसका अभिप्राय है सूर्य तथा मंगल एक दूसरे के आमने – सामने होंगे और पृथ्वी बीच में होगी। इसके परिणामस्वरूप मंगल पृथ्वी के निकट आयेगा जिसके कारण यह सामान्य से अधिक चमकीला दिखाई देगा तथा इसे जुलाई के अंत में सांय से सुबह तक देखा जा सकेगा। 27 – 28 जुलाई को आकाश में चमकदार मंगल ग्रह ग्रहण वाले चंद्रमा के बहुत निकट पहुंच जाएगा और इसे नंगी आंखों से भी बड़ी आसानी से देखा जा सकेगा। परंतु लाल ग्रह 31 जुलाई, 2018 को पृथ्वी के अत्यधिक निकट पहुंच जाएगा।

मंगल ग्रह 2 वर्ष तथा 2 महीने के अंतराल पर सामने आता है जब यह ग्रह पृथ्वी के निकट पहुंच जाता

है और अपेक्षाकृत अधिक चमकीला हो जाता है। मंगल की यह विपरीत स्थिति अगस्त 2003 में देखने में आई थी जिस समय लगभग 60,000 सालों में दो ग्रह निकटतम दूरी पर आ गए थे। मंगल का 31 जुलाई, 2018 को निकटतम आगमन 2 ग्रहों को अत्याधिक करीब ले आएगा और मंगल ग्रह 2003 के उपरांत अत्याधिक चमकीला दिखाई देगा।

27 जुलाई को भारतीय मानक समय के अुनसार 23 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा का आंशिक ग्रहण शुरू होगा। चंद्रमा धीरे – धीरे पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा और 28 जुलाई को भारतीय समयानुसार 1 बजे पूर्ण रूप से ग्रहण की स्थिति में आ जाएगा। 28 जुलाई को पूर्ण ग्रहण भारतीय समयानुसार 2 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा धीरे – धीरे पृथ्वी की छाया से बाहर आना शुरू हो जाएगा और आंशिक चंद्रग्रहण 28 जुलाई को भारतीय समयानुसार 3 बजकर 49 मिनट में पूरा हो जाएगा।

इस विशेष ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की अम्बरीय छाया के केंद्रीय भाग से गुजरेगा। इसके अलावा चंद्रमा अपने चरमोत्कर्ष पर होगा जिसका अभिप्राय है 27 जुलाई को अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर तथा अपनी कक्षा में धीमी गति से चल रहा होगा। पूर्ण चंद्रमा की इस धीमी गति से पृथ्वी के अम्बरीय छाया कोन की यात्रा करने में अधिक समय लगेगा तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे यह इस शताब्दी के संपूर्ण ग्रहण की सबसे लंबी अवधि होगी।

ऐसी लंबी अवधि के पूर्ण चंद्रग्रहण 1 घंटा 46 मिनट की कुल अवधि का 16 जुलाई, 2000 को तथा कुल 1 घंटा 40 मिनट की अवधि का 15 जून, 2011 को हुए थे।

संपूर्ण चंद्रग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, एशिया, रूस – उत्तरी हिस्से को छोड़कर, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमरीका के पूर्वी तथा अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी देखा जा सकेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए उठाए प्रभावी कदम

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और राशन की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि प्रदेश लगभग 18.37 लाख राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन समय पर उपलब्ध हो सके।

प्रदेश में इस समय लगभग 77. 20 लाख उपभोक्ता को 4,937 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस सुविधा के लिए सरकार ने इस वर्ष 220 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन

कपूर ने बताया कि योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को तीन दालें, सरसों व रिफाईंड तेल के अतिरिक्त नमक अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी, गंदम आटा तथा चावल भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार ने पहली बार दालों के मूल्य में पांच रुपये तक की कमी की है, जिससे प्रदेश के राशन कार्ड धारक लाभान्वित हुए हैं और सरकार की बचत भी हुई है।

आम जनता की सुविधा के लिए निगम के मुख्यालय में निदेशक की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जहां पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायतें ई – मेल complaint@himapurti.com तथा मोबाईल नम्बर 82199 – 29241 पर दर्ज करवा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा मोबाइल ऐप का भी आरम्भ किया है। इस ऐप को उपभोक्ता एण्डरॉयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से इपीडीएसएचपी नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के उपरान्त उपभोक्ता खाद्यान्न संबंधी पात्रता, कार्ड धारकों की सदस्यता आदि का पता घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता एप में अपना राशन कार्ड सेव करके रख सकता है, जिससे उपभोक्ता को अपना राशन कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस ऐप में एक सरल फीडबैक फार्म भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी उचित मूल्य की दुकान से संबंधित फीड बैक विभाग को आसानी से भेज सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्त को राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकान, खाद्य वस्तुओं की कमी या गुणवत्ता संबंधी शिकायत है तो वह शिकायत इस ऐप के माध्यम आसानी से विभाग को भेज सकता है। किसी परिवार को उसके सदस्यों की संख्या व पात्रता के अनुसार कितना राशन मिलेगा, इसका

ब्यौरा भी ऐप पर उपलब्ध है।

सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1967 टोल फ्री नम्बर भी स्थापित किया गया है, इस नम्बर पर भी उपभोक्ता राशन, एलपीजी, मिट्टी तेल संबंधी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल निवारण सुनिश्चित बनाया जा सके। विभाग द्वारा राज्य के 88.6 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों को आधार से जोड़ा जा चुका है, इससे जहां जाली राशन कार्ड धारकों पर अंकुश लगा है वहीं राशन के दुरूपयोग पर भी रोक लगने के साथ – साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आई है।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं के राशन क्रय संबंधी बिल व केशमेमों उनके मोबाइल पर उपलब्ध करवाए जाएं। इस दिशा में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सरकार के इन प्रयासों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आई है और उपभोक्ता सरकार की सस्ते राशन की इस सुविधा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' किसानों के लिए उम्मीद की किरण

मण्डी/शैल। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं और उनकी आर्थिकी कृषि पर निर्भर है। किसानों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी फसलों को जंगली जानवर तथा बेसहारा पशु काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनका खेतीबाड़ी के प्रति रूझान घट रहा था। अब किसानों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जिसमें 35 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा बाड़बंदी के लिए किया गया है।

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सौर उर्जा संचालित बाड़बंदी (सोलर फैंसिंग) का प्रावधान है। इसमें फैंसिंग वायर होती है और बीच में छोटे – छोटे स्प्रिंग लगे होते हैं। तार सोलर कंट्रोलिंग सिस्टम से जुड़ी होती है। जब कोई जानवर इसको छूता है अथवा तथा इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो तारों और स्प्रिंग पर दवाब पड़ने की वजह से करंट लगता है तथा हूटर बज जाता है। करंट का झटका जानलेवा नहीं होता, क्योंकि यह केवल सौर डीसी पावर कम एम्पीयर पर काम करता है। जानवर डर के कारण पीछे हट जाता है तथा पुन: सोलर फैंसिंग के समीप नहीं आता। सोलर फैंसिंग जानवरों व मनुष्यों दोनों के लिए सुरक्षित है।

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को समीप के कृषि कार्यालय में विषयवाद विशेषज्ञ के पास उपलब्ध प्रपत्र को भरकर देना होता है, जिसके साथ जमीन की नकल भी देनी पड़ती है। उसके बाद इसे स्वीकृति के लिए उप निदेशक, कृषि कार्यालय में भेजा जाता है। स्वीकृति प्रदान होने के बाद अधिकृत कम्पनी आकर प्राकलन तैयार करके किसान को सूचित करती है। यदि किसान सरकार द्वारा चलाई गयी योजना के तहत कुल लागत की 20 प्रतिशत राशि देने को तैयार है तो किसान को इसका ड्राफ्ट बनाकर कृषि विभाग को देना होता है, उसके बाद कम्पनी किसान की भूमि पर सोलर फैंसिंग लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर देती है और शेष राशि प्रदेश सरकार वहन करती है अगर किसान तीन या तीन से अधिक संख्या में सामूहिक तौर पर बाड़बंदी करवाना चाहे तो उन्हें 15 प्रतिशत राशि जमा करवानी पड़ती है तथा 85 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दी जाती है।

मण्डी जिला में भी किसानों द्वारा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाया जा रहा है तथा बेसहारा पशुओं, बंदरों तथा सूअरों की समस्या से निजात पाकर वे अपनी खेती का संरक्षण कर रहे हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत पधर उपमंडल में योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती का संरक्षण कर रहे हैं। उपमंडल में अभी तक योजना के तहत 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29 को स्वीकृति प्रदान हो चुकी है और इनमें से तीन पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं तथा शेष का कार्य प्रगति पर है।

पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने से फसलों को वास्तविकता में ही मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी तथा किसान का पुन: खेतीबाड़ी की ओर रूझान बढ़ेगा।

राज्यपाल द्वारा राज्य स्तरीय पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रास सोसायटी, शिमला के संयुक्त तत्वाधान में शिमला के निकट नेहरा में 69वें वन महोत्सव के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इस अभियान के तहत 5000 से अधिक पौधें रोपे गए। राज्यपाल और लेडी गर्वनर ने भी देवदार के पौधों का रोपण किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लोगों का आहवान किया कि पौधारोपण को जीवन का हिस्सा बनाएं। पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों में औपचारिकता न निभाकर इसे अपना कर्त्तव्य समझकर पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि वृक्ष प्रकृति का वरदान हैं, जिनका संरक्षरण जरूरी हैं। इसलिए हर व्यक्ति को विशेष अवसरों पर जैसे जन्मदिन, सालगिरह इत्यादि पर पौधारोपण करना चाहिए, जिससे यह कार्य जीवन का हिस्सा बन सके।

प्रदेश में तीन दिनों में रोपे गए 15 लाख पौधे:वनमंत्री

शिमला/शैल। वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार तीन दिन लगातार पौधरोपण अभियान के दौरान 15 लाख पौधे से भी अधिक पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि गत 12 से 14 जुलाई को प्रदेशभर में पौधरोपण का कार्य किया गया। वन विभाग के माध्यम से चलाये गए इस अभियान में समाज के हर वर्ग ने अभियान में भाग लिया। लगभग 80,000 से भी अधिक लोगों ने इस अभियान में भाग लिया। स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं, बजुर्गों व जवानों ने बढ़-चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा लिया। उत्तर में राज्य की जम्मू-कश्मीर सीमा से लेकर दक्षिण में यमुना तट तक, पूर्व में किन्नौर से लेकर पश्चिम में पंजाब की सीमा तक हर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य पूरे जोश के साथ किया गया। वन मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर सभी विधानसभा सदस्यों को पौधरोपण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। परिणामस्वरूप वन विभाग ने इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा कर लिया।

वनमंत्री ने कहा कि पौधरोपण का कार्य अभी भी जारी है और लक्ष्य से दो लाख अधिक तक पौधों का रोपण कार्य पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंडी वन वृत्त ने सबसे ज्यादा 2.75 लाख पौधे रोपित किये। प्रदेश में कुल 13 वन वृत्तों के 41 वन मंडलों में 600 स्थानों पर पौधारोपण किया गया। चम्बा वन मंडल 99,281 पौधों का रोपण कर अभियान में अव्वल स्थान पर बना हुआ है तथा आनी व रामपुर वन मंडल ने 81,369 व 80,059 पौधे लगा कर दूसरे एवं तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण में सबसे अधिक देवदार के छः लाख से भी अधिक पौधे रोपित किये गए। इसके अतिरिक्त चौड़ी पत्ती, अन्य शंकुधारी पौधों का भी रोपण किया गया।

गौरतलब है कि इस पौधरोपण अभियान की ऑनलाईन निगरानी की गई। सभी पौधारोपण क्षेत्रों में लगाए गए पौधों का ब्यौरा मोबाइल ऐप द्वारा साफ्टवेयर में भरने के लिए एक अधिकारी को अधिकृत किया गया था। पौधारोपण की प्रगति को सार्वजनिक तौर पर देखा गया। इसके अतिरिक्त वन विभाग के मुख्यालय में भी इसकी निगरानी की गई।

वृतवार पौधारोपण का ब्यौरा देते हुए वनमंत्री ने बताया कि चम्बा में 207961, धर्मशाला में 117271, हमीरपुर में 120931, बिलासपुर में 18910, मंडी में 275570, कुल्लू में 168180, रामपुर में 234723, शिमला में 127338, सोलन में 57087, नाहन में 153051, वन्य प्राणी (उत्तर) में 3400, वन्य प्राणी (दक्षिण) में 6600 तथा जी.एच.एन.पी. में 14905 पौधों का रोपण कार्य कर लिया गया है।

अधिकारियों को निर्देश जंगलों में स्थान चिन्हित कर फलदार पौधे लगाएं:महेन्द्र सिंह

मण्डी/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ग्राम पंचायत डरवाड़ के अनस्वाई गांव में उपमंडल स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर पीपल का पौधा रोपित किया ।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही प्रदेश में वन महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है जो कि पंचायत स्तर तक आयोजित किए जायेंगे।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जंगलों में कुछ स्थान चिन्हित कर फलदार पौधे लगाएं, जिससे जंगली जानवर गांव की ओर आकर्षित न हो। उन्होंने अधिकारियों को अपनी नर्सरियों में पौधे तैयार करने को भी कहा ।

उन्होंने लोगों से बरसात के मौसम में जंगलों तथा आस-पास के क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे रोपने का आहवान किया ।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानी परियोजना के तहत विदेशों से पौधे मंगवाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 300-400 रूपये प्रति पौधा है, जिन्हें बागवानों को 25 रूपये की दर से उपलब्ध करवाया जायेगा तथा पौधे रोपने व बाड़बंदी का व्यय भी सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

अरण्यपाल उपासना पटियाल ने बताया कि वन महोत्सव में 2 हैक्टेयर भूमि पर 800 पौधे रोपित किये गये । उन्होंने कहा कि मंडी जिला में इस वर्ष 106 स्थानों पर 3 लाख 55 हजार पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदेश में 393 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा:सरवीन चौधरी

धर्मशाला/शैल। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि जिला काँगड़ा के पालमपुर, नूरपुर व धर्मशाला के वन वृतों में इस वर्ष 700 हेक्टेयर भूमि पर अर्जुन, हरड़, बेहड़ा, आमला, शीशम, कचनार इत्यादि के लगभग 6.50 लाख पौधे लगाएं जाएंगे।

शाहपुर विधानसभा के तहत रेहलू के पट्टी गाँव में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान-2018 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इससे पहले उन्होंने स्वयं कार्यक्रम स्थल के पास अर्जुन का पौधा लगाया। इस तीन दिवसीय अभियान में जिला काँगड़ा में 152 हेक्टयर भूमि पर लगभग 1,30,000 पौधे लगाए जाएंगे ।

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिर्पोट के अनुसार प्रदेश में 393 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला काँगड़ा में 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इंसान के जीवन में वनों का विशेष महत्व है यह मानव जीवन के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार हैं।

सांसद ने किया पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ

सोलन/शैल। शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सभी से आग्रह किया है कि पौधरोपण के उपरांत पौधों की शिशुओं की तरह देखभाल करें ताकि ये पौधे विकसित होने पर पर्यावरण के सजग प्रहरी बन सकें। वीरेंद्र कश्यप सोलन विधानसभा क्षेत्र के सलोगड़ा के रेलवे स्टेशन पर आयोजित पौधा रोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के वन विभाग द्वारा किया गया।

इस अवसर पर प्रो. कश्यप ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा तथा अपने परिवेश को हराभरा रखने के लिए पौधरोपण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाकर हम अपनी भावी पीढ़ी को शुद्ध वातावरण देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सलोगड़ा रेलवे स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 350 पौधे दादू, आवंला, बेहड़ा व कचनार के लगाए गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोगड़ा की एनएसएस इकाई, स्थानीय महिला तथा युवक मंडलों ने भी पौधरोपण में भाग लिया।

पौधारोपण को जन-आन्दोलन बनाने के लिए लोगों का आहवान: मुख्यमंत्री

सिरमौर/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पौधारोपण को जन-आन्दोलन बनाने के लिए लोगों का आहवान किया ताकि प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के चुरवाधार में 69वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश का 67 प्रतिशत क्षेत्र में वन आवरण हैं प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ को 'गोत्र पेड़' के रूप में गोद लें तथा इसके संरक्षण व सुरक्षा में सहायता करे। इससे लोगों विशेषकर युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षित करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि पौधारोपण अभियान को केवल एक औपचारिक अवसर के रूप में नही मनाया जाना चाहिए, बल्कि रोपित किए गए पौधों को पेड़ के रूप में विकसित करने को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि प्रदेश में पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवदार व औषधीय पौधें का रोपण किया।

वनों को बनाया जायेगा रोजगार का साधन:किशन कपूर

धर्मशाला/शैल। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में वन संरक्षण पर बल देते हुए वनों को रोजगार और आजीविका का साधन बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य से अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किशन कपूर धर्मशाला के समीप चोहला गांव में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस मौके उन्होंने स्वयं देवदार का पौधा लगाया। उनके साथ साथ गांव के लोगों और अधिकारियों ने भी देवदार और बान के पौधे लगाए।

किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश में वन समृद्धि जन समृद्धि योजना शुरू की गई है, इसके जरिये लोगों को जड़ी बूटी इकटठा करने, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

किशन कपूर ने लोगों से वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। इससे पर्यावरण का संरक्षण तो होगा ही, भूमि कटाव भी रूकेगा और क्षेत्र की सुंदरता में वृद्धि होगी। इससे पर्यटन में भी इजाफा होगा। उन्होंने लोगों से लगाए गए पौधों के संरक्षण का ख्याल रखने का आग्रह किया।

भारतीय परम्परा में वृक्षों की पूजा से ही है प्रकृति की सुरक्षा: सैजल

सोलन/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रकृति के साथ मनुष्य का सह अस्तित्व है तथा प्रकृति की सुरक्षा से ही दीर्घकालिक विकास सम्भव है। डॉ. सैजल 69वें वन महोत्सव के तहत सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोहली में वृत स्तरीय पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ करने के उपरान्त उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

पौधारोपण कार्यक्रम में बोहली में तीन हैक्टेयर क्षेत्र में दादू, आंवला, बहेड़ा तथा जामुन के 3300 पौधे लगाए गए। डॉ. सैजल ने कहा कि वृक्ष न केवल पृथ्वी पर सभी जीवों के सुरक्षित अस्तित्व अपितु शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा शुद्ध पर्यावरण के लिए भी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि वनों को सुरक्षित रखकर ही पृथ्वी को भावी पीढ़ीयों एंव अन्य जीव जंतुओं के निवास के लिए बचाया जा सकेगा। भारतीय संस्कृति एवं परम्परा वृक्षों की पूजा पर बल देती है। इसका मुख्य कारण प्रकृति की सुरक्षा ही है।

अरण्यपाल हर्षवर्धन कथूरिया ने बताया सोलन तथा नालागढ़ वन मण्डलों में विभिन्न प्रजातियों के 62,000 पौधे लगाए जा रहे हैं।

सरकार उपेक्षित क्षेत्रों के विकास को प्रदान कर रही है सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला जिले के बलघार में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी, जो अभी तक विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा वह स्वयं एक सादगीपूर्ण पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखते है और आम जनमानस की विकासात्मक जरूरतों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया और वह भी बिना किसी आय सीमा के। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस एक ही निर्णय से प्रदेश के 1.30 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार बजट में पर्याप्त बजट प्रावधान के 30 नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष में कुछ उनके मित्र उनके दिल्ली दौरे तथा केन्द्रीय मंत्रियों से राज्य की विकासात्मक जरूरतों पर विस्तृत चर्चा करने तक को नहीं पचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लिए 4365 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में सफल हुई है और अब इन नेताओं के पास कहने को कुछ शेष नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इस बात को भली-भांति समझते हैं कि पिछली राज्य सरकार ने पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के लिए क्या किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अकेले बलघार में उन्होंने 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं रखी। उन्होंने कहा कि चौपाल निर्वाचन सभा क्षेत्र की पिछले कई वर्षों से विकास के मामले में अनदेखी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हेली टैक्सी सेवा आरम्भ की है और देश में पहली बार राज्य सरकार ने शिमला से चण्डीगढ़ के लिए हेली टैक्सी के रूप में सप्ताह में तीन दिन राज्य हेलीकॉप्टर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए 69 उच्च मार्ग स्वीकृत किए हैं और राज्य सरकार ने 54 राष्ट्रीय

राजमार्गों की डीपीआर भी तैयार कर ली हैं ताकि परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र में यूपीए का कार्यकाल अनेक घोटालों व भ्रष्टाचारों वाला रहा है। केन्द्र में मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भारत देश के प्रमुख देशों में मुख्य शक्ति के रूप में उभरा है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत घोड़ना तथा घूण्ड के श्रीगुली, कडाहरण, घासीगांव तथा मठोग के लिए 83.83 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने 217 लाख रुपये की लागत से निर्मित घलाणा से किशोर सड़क, 82 लाख रुपये की लागत से निर्मित देहा से किशोरी सड़क, 34 लाख रुपये के टिक्कर से दुनखड़ सड़क तथा 90 लाख रुपये की लागत से निर्मित शलोआ से कथयोग सड़क के लोकार्पण किए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 200 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली भुल्टी से पुन्दर सड़क के भाग कुठार-पुन्दर सड़क की आधारशिला के अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहा में 70 लाख रुपये के इंडोर एडवेंचर हॉल, 352 लाख रुपये के मेहा से टाली-खोलना सड़क को पक्का करने, 185 लाख रुपये की लागत से ठियोग तहसील के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बासाधार की आधारशिला, 78 लाख रुपये की लागत से धमन केंची से धार (सूजना) सड़क को पक्का करने, टाली में 153 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धार टरपणू, ग्राम पंचायत बलघार में भराड़ा खड्ड से कटीयाणा के लिए पाईप के माध्यम से 45.75 लाख रुपये की लागत की सिंचाई योजना तथा ग्राम पंचायत कुठार में दवाड़ा खड्ड से खारकु गांव के लिए 67.90 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना की आधारशिलाएं रखी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए घागल में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने तीन सड़कों के लिए पांच-पांच लाख रुपये, आयुर्वेदिक औषधालय के लिए 15 लाख रुपये, कनोली में प्राथमिक पाठशाला खोलने, उच्च पाठशाला धमयाणा को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टाली के लिए 50 लाख रुपये, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घूण्ड में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने, टाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलघार को 30 बिस्तरों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। उन्होंने पुलिस पोस्ट देहा को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने तथा बासाधार में बागवानी उप केन्द्र खोलने की भी घोषणा की।

बलसन घूण्ड कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51000 रुपये का चेक भेंट किया।

सभी पात्र उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर उपलब्ध हो रहा राशन: उपायुक्त

मंडी/शैल। जिला स्तरीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक को संबोधित करते हुए ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तय लक्ष्य के विपरीत 5,12,813 पात्र जनसंख्या का चयन किया गया है जिन्हें प्रति माह तीन किलोग्राम गंदम प्रति व्यक्ति दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर तथा दो किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर तथा 20 किलोग्राम गंदम प्रति परिवार दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन प्राथमिक परिवारों का चयन उक्त अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उनको खाद्यान्नों के अतिरिक्त तीन सदस्य तक वाले परिवारों को दो किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर और तीन किलोग्राम गंदम 7 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि फरवरी, 2018 से जून, 2018 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला मंडी के उपभोक्ताओं को लगभग 60.140 किलोग्राम चावल, 78.52 क्विंटल गंदम आटा तथा 84.596 क्विंटल गंदम का वितरण किया गया। इसी प्रकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समान अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 784 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से लगभग 47 करोड़ 56 लाख रुपए की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गयी, जिससे तीन लाख से अधिक राशन कार्ड धारक लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त 643 किलो लीटर मिट्टी तेल तथा 4,45,402 रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए गए।

उन्होंने कहा कि राज्य अनुदानित योजना के अंतर्गत मंडी जिला में माह फरवरी, 2018 से जून, 2018 तक लगभग 13,165 क्विंटल दाल चना, 2,314 क्विंटल राजमाह, 442 क्विंटल मसर, 6,220 क्विंटल दाल मलका, 13,215 क्विंटल दाल उड़द, 118 क्विंटल सफेद चना, 118 क्विंटल दाल मूंग साबुत, 13,72,675 लीटर सरसों तेल तथा 4,05,308 लीटर रिफाईंड तेल का वितरण अनुदानित दरों पर उपभोक्ताओं को किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिला में उपलब्ध करवाई जा रही आवश्यक वस्तुओं व राशन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की गई है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान लगभग 2,233 निरीक्षण किए गए जिनमें 662 उचित मूल्य की दुकानें भी शामिल हैं। इस दौरान लगभग एक लाख 37 हजार रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई।

उन्होंने कहा कि मंडी जिला में उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नही रखा जाएगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि राशन वितरण में आने वाली तकनीकी खामियों को समय रहते दुरूस्त करें और बायोमीट्रिक प्रणाली के अतिरिक्त वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) सहित अन्य विकल्प अपनाते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को राशन वितरण सुनिश्चित करें।

डेंगू के 143 में से 129 रोगी स्वस्थ

बिलासपुर/शैल। नोडल अधिकारी एवं एमओएच डॉ परविन्द्र शर्मा ने जिला में फैले डेंगू रोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया 14 जुलाई को डेंगू के दो नए मामले दर्ज किए गये। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डेंगू से पीड़ित 14 रोगियों का ईलाज चल रहा है। जिनमें से डेंगू से पीड़ित 12 रोगियो का ईलाज उनके घरों में चल रहा है तथा 2 रोगी हस्पताल में दाखिल है। उन्होंने बताया कि अब तक 143 डेंगू के मामले दर्ज किए गए जिनमें से 129 रोगी स्वस्थ हो चुके है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा विभिन्न वार्डों में लोगों के घरों में पानी की टंकियों, कुलरों और जल भंडारण के बर्तनों को खाली करवाकर उन्हें साफ करवाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लोगों को अपने घरों और आस-पास की साफ-सफाई रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढक कर और ओडोमोस इत्यादि कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करें तथा घरों के अंदर भी कीटनाशक स्प्रे करना सुनिश्चित बनाए ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।

जलजनित रोगों पर उपायुक्त ने किया किया लोगों को सचेत

बिलासपुर/शैल। उपायुक्त संदीप कुमार ने बरसात के मौसम में रोगों से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर देने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संबंधित उपमंडलाधिकारियों का सहयोग लेकर लोगों को रोगों से बचाव के ऐहतियाती कदमों बारे शिक्षित करने एवं स्वास्थ्य बारे जागरूकता संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है।

संदीप कुमार यहां आंत्रशोध, हैजा तथा डेंगु नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास अभिकरण और सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बोल रहे थे।

संदीप कुमार ने जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी पेयजल योजनाओं तथा जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरीनेशन की प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए, ताकि मानसून के चलते प्रदूषित जल की सम्भावनाओं को कम करके जल से उत्पन्न रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि आंत्रशोध व हैजा जैसे संक्रामक रोगों से बचने के लिये अपने परिवेश की स्वच्छता सबसे अहम रहती है। बरसात के मौसम में अपने आस-पास की स्वच्छता रखने के साथ साथ उबला पानी उपयोग करना चाहिये।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि आशा-वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ओआरएस पैकेट वितरित करने के साथ-साथ क्षेत्र में डायरिया रोग से ग्रस्त बच्चों को उचित निदान के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी यह तय बनाने को कहा कि स्कूली स्तर पर अध्यापक बच्चों को शारीरिक सफाई के लिए जागरूक करें।

उपायुक्त ने जिलावासियों से जल जनित रोगों के प्रति सचेत रहने तथा बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूषित पेयजल का सेवन करने से आन्त्रशोध व डायरिया इत्यादि बीमारियों के फैलने की सम्भावना प्रबल हो जाती है, जो बच्चों को अधिक प्रभावित करती है।

उन्होंने सभी लोगों से जल स्त्रोतों को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करने तथा अपने आस-पास के परिवेश में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से अपने घरों में पानी की टंकियों की समय-समय पर सफाई करने और दूषित पेयजल एवं खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने का भी आग्रह किया।

बैठक में जिला में क्षय रोग निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के तहत जिला को पूर्णत: क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत लोगों के घर-घर जाकर टीबी के रोगियों को खोजा जाएगा और उनका इलाज सुनिश्चित बनाया जाएगा।

जिला चिकित्सा अधिकारी डा. राजेश गुलेरी ने डायरिया नियंत्रण पखवाडे के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.आरएसराणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ज्वालामुखी में 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

कांगड़ा/शैल। कांगड़ा जिला में व्यावसायिक कार्यो के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मुहिम छेड़ रखी है। इस कड़ी में विभाग के दल ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में ज्वालामुखी में होटल, ढाबों, सब्जी विक्रेताओं और करियाना की दुकानों की जांच की । जांच दल में जिला खाद्य नियंत्रक के साथ कांगड़ा, देहरा, प्रागपुर, फतेहपुर और रैत के खाद्य निरीक्षक थे।

नरेंद्र धीमान के बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कई ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों का धड़ाधड़ प्रयोग किया जा रहा था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर 14 गैस सिलेंडर जब्त किए। इसके अलावा गग्गल में भी टीम ने छापेमारी की, जहां घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरने के अवैध धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने कहा कि विभाग समय-समय पर जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके जमाखोरों पर शिकंजा कस रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

अमित शाह का दौरा रद्द होना प्रदेश नेतृत्व को झटका

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हिमाचल का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है जबकि प्रदेश भाजपा और जयराम सरकार लम्बे अरसे से इस दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे। बल्कि ज्वालामुखी में आयोजित की गयी दो दिवसीय बैठक भी इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा थी। इस परिदृश्य में शाह के दौरे का स्थगित होना राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बनना स्वभाविक है। लोकसभा के चुनाव अगले वर्ष मई में होना तय है लेकिन इस बात के ठोस संकेत उभरते जा रहे हैं कि चुनाव समय से पूर्व ही हो जायेंगे। क्योंकि इसी वर्ष के अन्त में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होना तय है। इन राज्यों में लम्बे अरसे से भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन इस बार इन राज्यों में हुए कुछ विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों में भाजपा को करारी हार मिली है। इस हार का सबसे बड़ा लाभ भी कांग्रेस को ही मिला है क्योंकि यहां भाजपा का राजनीतिक विकल्प कांग्रेस ही है। फिर लोकसभा चुनाव के लिये सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है क्योंकि यदि इकट्ठा होकर विपक्ष भाजपा का सामना करेगा तभी तो बाद में क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में अपने वर्चस्व की मांग कर पायेंगे। भाजपा विपक्षी एकता की संभावना से अन्दर से घबरायी हुई है और इसे तोड़ने के लिये भाजपा ने सोशल मीडिया का एकमात्र फोकस राहूल और नेहरू परिवार के खिलाफ कर दिया है कि यदि एक झूठ को सौ बार बोलेंगे तो वह सच्च बन जायेगा लेकिन अब जब सोशल मीडिया की कुछ साईटस का सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है और इस संज्ञान के बाद पोस्टकार्ड मीडिया साईट के संस्थापक की गिरफ्तारी भी हो गयी है इससे सोशल मीडिया पर आधारित होने की धारणा को झटका भी लगा है क्योंकि इन दिनों अमित शाह सबसे अधिक अपने सोशल साईट कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। हिमाचल में भी इसकी तैयारियां चल रही थी लेकिन यहां आईटी सैल के प्रमुख के त्यागपत्र के कारण यह गणित गड़बड़ा गया है।

इस सारी वस्तुस्थिति को सामने रखते हुए शाह के दौरे का रद्द हो जाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय भाजपा के शीर्ष केन्द्रिय नेतृत्व का पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर ही केन्द्रित चल रहा है। मोदी शाह की कार्यप्रणाली की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि यह लोग अपने सूचना तन्त्र पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस तन्त्र में केन्द्र सरकार की ऐजैन्सीयों के अतिरिक्त और भी कई ऐजैन्सीयां फील्ड में सर्वे में जुटी हुई है। हिमाचल में भी पिछले एक माह में ऐसी दो टीमें प्रदेश का सर्वे कर गयी हैं। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक इन सर्वो में हिमाचल से चारों सीटें फिर से मिलने की संभावना नही मानी जा रही है। इसमें यह भी सामने आया है कि पिछले लोकसभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा के पास वीरभद्र के खिलाफ आयकर, सीबीआई और ईडी में चल रहे मामले एक बड़ा हथियार थे। इन्ही के सहारे यह आरोप लगाये गये थे कि वीरभद्र के तो पेड़ो पर भी पैसे उगते हैं लोकसभा चुनावों के बाद जब विधानसभा चुनाव आये तब वीरभद्र सरकार की कार्यप्रणाली मुद्दा बन गयी जिसमें गुड़िया जैसे प्रकरणों ने आग में घी का काम किया। भ्रष्टाचार को लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंपे गये और सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय प्रचारित कर दिया गया तथा भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिल गया। लेकिन आज यह कोई भी हथियार भाजपा इस्तेमाल नही कर सकती क्योंकि इन मामलों में भाजपा सरकार की केन्द्र से लेकर राज्य तक करनी उनकी कथनी से एकदम भिन्न रही है। बल्कि आज उल्टे यह मामले भाजपा से जवाब मांगेगे।

ऐसे में इन लोकसभा चुनावों में सबकुछ राज्य सरकार की करनी और मुख्यमन्त्री की अपनी कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा। आज जयराम सरकार के इस दौरान लिये गये फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा की जाये तो इनका बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नही दिख पाया है। जयराम किस तरह के सलाहकारों से प्रशासन और राजनीतिक मसलों पर घिरे हुए हैं उस पर तो वीरभद्र की टिप्पणी ही सबसे स्टीक बैठती है। जब उन्होंने यह कहा कि यह लोग गद्दी के लिये खतरा हो सकते हैं। स्वभाविक भी हैं जिस मुख्यमन्त्री को अपने मुख्य सचिव की रक्षा यह कहकर करनी पड़े कि दिल्ली में उनके खिलाफ क्या है इससे उनका कोई सरोकार नही है तो यह टिप्पणी एक तरह से केन्द्र के ही खिलाफ हो जाती है। आज यह आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि शीर्ष प्रशासन की निष्ठायें शायद मुख्यमन्त्री से ज्यादा कहीं और हैं खली प्रकरण और दीपक सानन को स्टडी लीव देने जैसे कई मामले आने वाले समय में सरकार से जवाब मांगेगे। लोकसभा प्रत्याशीयों को लेकर भी अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नही है कि सभी पुराने जीते हुओं को ही फिर से चुनाव में उतारा जायेगा या इनमे कोई फेरबदल होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां किसी न किसी कारण से टलती जा रही हैं। ज्वालामुखी की बैठक में शान्ता, धूमल और नड्डा का शमिल न होना एक अलग ही संदेश दे गया है। अभी जयराम ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह मन्त्रीयों के रिपोर्ट कार्ड पर बराबर नज़र रख रहे हैं। बल्कि इस कथन के बाद मन्त्रीमण्डल में फेरबदल की अटकलें तक चल पड़ी थी। माना जा रहा था कि शाह के दौरे के दौरान इन अटकलों पर स्थिति साफ हो जायेगी। लेकिन अब शाह के दौरे के दौरान इन अटकलों पर स्थिति साफ हो जायेगी। लेकिन अब शाह के दौरे के रद्द होने से यह भी चर्चा चल पड़ी है कि लोकसभा चुनावों के परिदृश्य में केन्द्र प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड पर भी नज़र रख रहा है। सूत्रों की माने तो जिस बैठक में शाह का दौरा रद्द हुआ है उसी बैठक में शान्ता कुमार को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दिये जाने पर भी विचार हुआ है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश की भाजपा राजनीति में कई समीकरण बदलेंगे। शाह का दौरा रद्द होना मुख्यमन्त्री के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है।

आसान नही होगा अगले मुख्य सचिव और डीजीपी का चयन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वर्तमान मुख्य सचिव विनित चौधरी दो माह बाद सितम्बर में सेवानिवृत हो रहे हैं। उनके बाद प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा इसको लेकर अभी से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चौधरी 1982 बैच के अधिकारी हैं इनके बाद 1983 बैच के चार अधिकारी उपमा चौधरी, डा. आशा राम सिहाग, वीसी फारखा और डा. भारती सिहाग हैं 1984 बैच में तरूण श्रीधर और अरविंद मेहता हैं। इसके बाद 1985 बैच के चार अधिकारी हैं। 1987 बैच तक के सारे आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में 1983 बैच के केवल वीसी फारखा कार्यरत हैं बाकी सभी केन्द्र सरकार में हैं। 1984 बेच के भी दोनो अधिकारी केन्द्र मे हैं। 1985 बैच के तीन अधिकारी प्रदेश में कार्यरत है जिनमें डा. बाल्दी मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव हैं। इन्ही में से कोई प्रदेश का अगला मुख्य सचिव होगा। चर्चाओं के अनुसार 1985 बैच के जो अधिकारी प्रदेश में कार्यरत है उन्ही में से किसी की नियुक्ति हो जायेगी क्योंकि 1983 बैच के फारखा वीरभद्र के समय में मुख्य सचिव रह चुके हैं और उनकी नियुक्ति प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में होना तय मानी जा रही है।

लेकिन जब वीरभद्र के शासनकाल में विनित चौधरी को नज़रअन्दाज करके फारखा को मुख्य सचिव बनाया गया था जब चौधरी और दीपक सानन ने इस नियुक्ति को कैट में चुनौती दी थी। क्योंकि उस समय इस चयन के लिये जो सोलह अधिकारियों की सूची तैयार की गयी थी और तर्क दिया गया था कि यह सब अतिरिक्त मुख्य सचिव होने के नाते मुख्य सचिव के समकक्ष हो जाते हैं उस समय चौधरी ने कैट में यह कहा था कि That the note artificially expands the list of officers who are eligible to be considered for appointment as Chief Secretary by including officers holding posts of Additional Chief Secretary that have been created in contravention of the IAS Pay Rules and the IAS Cadre Rules and Government of India instructions disallowing creation of posts in the apex grade under the 2nd proviso to Rule 4(2) of the IAS Cadre Rules.

That the note indicates that all 16 officers have been placed in the apex grade after due screening by the screening committee which is factually incorrect because respondent No. 3 Sh VC Pharka along with Respondent no 4, was granted the Chief Secretary's grade without any consideration by the Screening Committee and was, therefore, not eligible for being considered for appointment to the post of Chief Secretary.

That the note fails to draw attention to the fact that recommendation of the Civil Services Board was now mandatory for making any appointment to cadre posts after amendment in the IAS (Cadre Rules) in pursuance of the Supreme Court's judgment in the TSR Subramanian case and consequential amendments in the IAS Cadre Rules.

Two officers of the 1983 batch viz Upma Chawdhry and Vidya Chander Pharka were promoted to the Chief Secretary's grade on 04.03.2014 by upgrading two posts of Principal Secretary to the Govt out of which one post was to re-convert to the post of Principal Secretary on 30.4.2015. The apex scale was released without any assessment by the Screening Committee. As per information obtained under RTI, no information about the meeting of the Screening Committee is available with the State Govt. इस तर्क के आधार पर तो आज भी वही स्थिति खड़ी है। मुख्य सचिव के बाद केवल तीन ही अन्य अधिकारी प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं और यह दायरा 1983 बैच में ही पूरा हो जाता हैं

कैट में जो तर्क चौधरी ने रखा था लगभग उसी तर्ज पर कैग रिपोर्ट में भी पहली बार अतिरिक्त मुख्य सचिवों की इतनी लम्बी सूची पर आपत्ति उठाई गयी है। जब मुख्य सचिव सहित केवल तीन ही अन्य अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं तो फिर इस बार भी मुख्य सचिव के लिये चयन का दायरा कैसे बढ़ पायेगा। जब वर्तमान मुख्य सचिव अगले मुख्य सचिव के चयन के लिये फाईल तैयार करेंगे तो वह अपनी ही याचिका में उठाये तर्क से बाहर कैसे जा पायेंगे। इसके लिये माना जा रहा है कि इस बार चयन का दायरा 1983 बैच के अधिकारियों तक ही सीमित होकर रह जायेगा। क्योंकि तब मुख्यमन्त्री 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत करने का दम नही दिखा पा रहे हैं तो मुख्य सचिव के चयन के लिये वह 1985 के अधिकारियों तक कैसे आ पायेंगे इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है।

ठीक ऐसी ही स्थिति डीजीपी के पद के चयन के लिये होने जा रही है। गुड़िया कांड के परिदृश्य में सामेश गोयल को डीजीपी के चयन के पद से हटाकर एसआर मरड़ी को डीजीपी बनाया गया था। लेकिन जब इसी कांड के अभियुक्त शिमला के पूर्व एसपी डी डब्ल्यू नेगी को मिलने वीरभद्र के पूर्व सुरक्षा कर्मी पदम सिंह के साथ कैथु जेल में मिलने पंहुच गये थे और उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए डीजीपी जेल गोयल ने जेल अधीक्षक से जवाब तलब कर लिया जब यह विवाद कुछ और ही रूख ले गया। इसके बाद कसौली गोली कांड में फिर पुलिस की फजीहत हुई। इसी सबको सामने रखते हुए फिर नये डीजीपी की तलाश की चर्चाएं शुरू हो गयी। इन चर्चाओं के बीच संजय कुण्डु का नाम सामने आया। यहां तक चर्चाएं बाहर आ गयी की कुण्डु को प्रदेश में लाने के लिये मुख्यमन्त्री कार्यालय से पत्र लिखा गया। मुख्यमन्त्री कुण्डु के घर दिल्ली में नाश्ते पर भी हो आये है। यह भी चर्चा का विषय बन गया। यह प्रचारित हो गया कि कुण्डु को सचिवालय में मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में तैनाती दी जायेगी। इन्ही चर्चाओं के बीच कुण्डु दिल्ली से पद मुक्त भी हो गये। लेकिन पदमुक्त होने के साथ ही छुटटी पर भी चले गये।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने 2006 के प्रकाश सिंह और एन के सिंह के मामले में आये फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारें अब कार्यकारी डीजीपी के रूप में कोई नियुक्ति नही कर सकेंगे। डीजीपी की नियुक्ति के लिये सरकार को तीन माह पहले पांच नामों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। आयोग उसमें से तीन नामों का चयन करके राज्य सरकार को भेजेगा और सरकार को उन्ही तीन नामों में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करना होगा। ऐसे में जो यह माना जा रहा था कि कुण्डु पर मुख्यमन्त्री का भरोसा बन गया है और वह ही आने वाले दिनों में प्रदेश के डीजीपी होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद यह संभावना समाप्त हो गयी है। ऐसे में अब प्रदेश को नया डीजीपी मिल पाता है या नहीं इसको लेकर स्थिति उलझ गयी है।